

बिजनेस

श्री बालाजी ग्रुप को मिला दो पूर्व अध्यक्षों का समर्थन

वाणिज्य संवाददाता

जयपुर। विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के 17 सितम्बर को रोड नंबर एक स्थित विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन में सुबह दस से शाम चार बजे तक होने वाले चुनाव में बालाजी ग्रुप ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। श्री बालाजी ग्रुप ने वीकेआई और अजमेर रोड के ट्रांसपोर्ट व्यवसाइयों से सम्पर्क किया। बालाजी ग्रुप को विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओम शाह और महेन्द्र सिंह जादौन ने समर्थन दिया है। बालाजी ग्रुप से महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे जगदीश यादव निवर्तमान महासचिव हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में संगठन का विस्तार किया है। अब यह ग्रुप ट्रांसपोर्टनगर योजना का लाभ सभी पात्र ट्रांसपोर्ट व्यवसाइयों को दिलाने के लक्ष्य पर चुनावी मैदान में है। चुनाव अधिकारी जगदीश सोमानी ने बताया कि चुनाव में 800 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। श्री बालाजी ग्रुप से अनिल सोनी अध्यक्ष तथा जगदीश यादव महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ग्रुप का चुनाव चिन्ह न्याय की देवी है। कोषाध्यक्ष पद के लिए गणपत चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए माल सिंह खंगारोत, संयुक्त सचिव पद के लिए महेश चंद वैष्णव, प्रचार मंत्री के लिए विजय कुमार शर्मा, संगठन मंत्री के लिए भंवर सिंह शेखावत चुनावी मैदान में हैं। कार्यकारिणी सदस्य के लिए इस ग्रुप से भागीरथ चौधरी, सत्यनारायण शर्मा, सुरेन्द्र सिंह नरुका, रामस्वरूप पिलानिया, बजरंग सिंह नाथावत, राजेश कुमार गुप्ता, लालाराम मीणा, किशन सिंह हरिराम विश्णोई, बाबूलाल यादव, बिजेन्द्र सिंह शेखावत, महेश खंडेलवाल, प्रदीप सिंह राठौड़ किस्मत आजमा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को मोहलत देने से किया इनकार

अदालत को प्रयोगशाला न समझें

वाणिज्य संवाददाता

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 966 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए और दो माह का समय देने की अपील की गई थी। सहारा प्रमुख ने न्यायालय से 1,500 करोड़ रुपए की राशि में से शेष बची 966 करोड़ रुपए की राशि को जमा कराने के लिए 11 नवंबर तक का समय देने की अपील की थी। न्यायालय ने उनकी इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह शीर्ष अदालत का कानून से खेलने के लिए एक प्रयोगशाला की तरह उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायालय ने आधिकारिक परिसमापक को समूह की एंबी वैली परियोजना की नीलामी पर तय समय के अनुसार ही बढ़ने का निर्देश दिया। समूह की महाराष्ट्र की एंबी वैली संपत्ति का मूल्य 37,392 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही न्यायालय ने रॉय की 11 नवंबर तक का समय देने की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब रॉय ने बताया कि उन्होंने सेबी-सहारा खाते में 533.20 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं और वह शेष 966.80 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान 11 नवंबर की तारीख वाले चेकों के जरिए करना चाहते हैं। न्यायालय ने कहा कि सहारा प्रमुख ने सिर्फ अतिशयोक्तिपूर्ण और वाकपटुता वाले बयान दिए हैं लेकिन यह पूरी राशि अब तक जमा नहीं कराई गई है। न्यायालय ने 25 जुलाई को सहारा प्रमुख को 1,500 करोड़ रुपए की राशि सात सितंबर तक सेबी-सहारा खाते में जमा करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने कहा था कि उसके बाद ही रॉय निवेशकों को बकाया राशि के पूर्ण भुगतान के लिए 18 माह का और समय मांगने की याचिका पर बहस कर सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आगे की 11 नवंबर की तारीख के चेकों के लिए मंजूरी देना न्याय का उपहास बनाने जैसा होगा। यह एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति से सहानुभूति दिखाने जैसा होगा जो निश्चित रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा, वह अगर यह समझते हैं कि वह कानून के साथ खेल सकते हैं, तो यह उनकी गलत धारणा है। पीठ में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई तथा और न्यायमूर्ति ए के सीकरी भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि सहारा प्रमुख शीर्ष अदालत को एक प्रयोगशाला की तरह मान रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आगे की 11 नवंबर की तारीख के चेकों के लिए मंजूरी देना न्याय का उपहास बनाने जैसा होगा। यह एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति से सहानुभूति दिखाने जैसा होगा जो निश्चित रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा, वह अगर यह समझते हैं कि वह कानून के साथ खेल सकते हैं, तो यह उनकी गलत धारणा है। पीठ में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई तथा और न्यायमूर्ति ए के सीकरी भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि सहारा प्रमुख शीर्ष अदालत को एक प्रयोगशाला की तरह मान रहे हैं।

नई दिल्ली। फरवरी 2018 तक टेलिकॉम कंपनियों को अपने सभी कस्टमर के मोबाइल नंबर को आधार से वैरिफाई करना है। जिन कस्टमर ने ऐसा नहीं कराया तो उनका नंबर डिएक्टिवेट भी हो सकता है। कस्टमर की इन्हीं मजबूरियों का फायदा कुछ टेलिकॉम कंपनियां उठा रही हैं। जिसकी शिकायत यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) तक पहुंची है। मामले की जांच करने पर अथॉरिटी ने कंपनियों को चेतावनी भी दी है। अथॉरिटी ने कंपनियों को अलर्ट करते हुए कहा है कि वह कस्टमर को परेशान न करे, अगर वे नहीं सुधरेंगे, तो उन पर एक करोड़ रुपए तक पेनल्टी भी लगाई जाएगी। फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बांटा 16 करोड़ रुपए का ऋण

वाणिज्य संवाददाता

जयपुर। राजस्थान में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों को अब तक 16 हजार 719 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 17 हजार 324 करोड़ रुपए की लागत वाले 27 लाख 90 हजार 977 प्रस्तावों को मंजूर किया गया है। इसमें से अब तक 16 हजार 719 करोड़ रुपए के ऋण



वितरित किए गए हैं। मंजूर किए गए प्रस्तावों में सबसे अधिक शिशु श्रेणी के हैं इनमें 5 हजार 432 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत कर 5 हजार 273 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी में 50 हजार रुपए तक, किशोर श्रेणी में 50 हजार से 5 लाख रुपए तक और तरण श्रेणी में 5 से 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जा सकते हैं।

बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार

सैंसेक्स 254 अंक चढ़ा

वाणिज्य संवाददाता

नई दिल्ली। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों से हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को घरेलू स्टॉक मार्केट की तेज शुरुआत हुई थी। सैंसेक्स 147 अंक बढ़कर 32029 अंक पर खुला वहीं निफ्टी 51 अंक की तेजी के साथ 10057 अंक पर खुला था। कारोबार के अंत में आज सैंसेक्स 254.98 अंक यानि 0.80 फीसदी बढ़कर 32,137.14 पर और निफ्टी 81.50 अंक यानि 0.81 फीसदी बढ़कर 10,087.55 के स्तर पर बंद हुआ है।

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 1.1 फीसदी बढ़कर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी के मिडकैप 100 इंडेक्स में 1 फीसदी की तेजी आई है। बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स 1 फीसदी तक मजबूत होकर बंद हुआ है।

निफ्टी का ऑटो इंडेक्स भी रहा मजबूत

सोने-चांदी की चमक हुई फीकी



वाणिज्य संवाददाता

नई दिल्ली। त्रैहारी मौसम से पहले सर्राफा कारोबारियों की ग्राहकी बढ़ने के बावजूद वैश्विक स्तर पर पीली धातु की कीमतों में रही गिरावट से दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 150 रुपए लुढ़ककर 30,850 रुपए प्रति दस ग्राम पर आ गया।

सुस्त औद्योगिक मांग से चांदी भी 50 रुपए फिसलकर 41,650 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लंदन का सोना हाजिर 1.55 डॉलर टूटकर 1,326.95 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।



ऑटो, एफएमसीजी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, रियल्टी, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्युरेबल्स और ऑयल एंड गैस शेयरों में जमकर खरीदारी हुई है। निफ्टी के ऑटो इंडेक्स में 1.2 फीसदी, एफएमसीजी इंडेक्स में 1.4 फीसदी, मीडिया इंडेक्स में 1.2 फीसदी, मेटल इंडेक्स में 1 फीसदी, फार्मा इंडेक्स में 2.2 फीसदी और पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1.3 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।

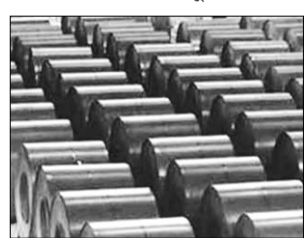
1 महीने में 18 फीसदी तक बढ़े मेटल स्टॉक

वाणिज्य संवाददाता

नई दिल्ली। पिछले एक महीने के दौरान सेक्टर इंडेक्स के बीच मेटल सेक्टर इंडेक्स का रिटर्न सबसे शानदार रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मेटल कीमतों में पिछले कुछ समय से जारी बढ़त की वजह से सेक्टर के लिए आउटलुक बेहतर हो गए हैं। जिसकी वजह से स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिली है। वहीं ब्रोकरेज हाउस ने भी कई मेटल स्टॉक्स में आगे भी ग्रोथ का अनुमान दिया है।

पिछले एक महीने के प्रदर्शन पर नजर डालें तो मेटल सेक्टर इंडेक्स में सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिला

है। एक महीने के दौरान मेटल सेक्टर इंडेक्स में 8.62 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है। दूसरे नंबर पर



रियल्टी सेक्टर इंडेक्स रहा है जिसमें करीब 6 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है। बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स का रिटर्न 5 फीसदी से नीचे रहा है। एक महीने के दौरान मेटल सेक्टर में

शामिल 15 स्टॉक्स में से 4 स्टॉक्स में 10 फीसदी से ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। एमओआईएल में 18 फीसदी से ज्यादा, नाल्को में 18 फीसदी, जेएसडब्लू स्टील में 15.5 फीसदी औप वैलस्पन कॉर्प में 10 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई है।

मेटल स्टॉक्स में तेजी ग्लोबल मार्केट में मेटल कीमतों में बढ़त की वजह से देखने को मिली है। केडिया कमोडिटी के अजय केडिया के मुताबिक मेटल कीमतों में पिछले कुछ समय से बढ़त देखने को मिली। चीन सहित कई देशों में पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए यूनिट्स बंद की जा रही हैं।

सिम वैरिफिकेशन के नाम पर हो रहा है फ्राँड

वाणिज्य संवाददाता

नई दिल्ली। फरवरी 2018 तक टेलिकॉम कंपनियों को अपने सभी कस्टमर के मोबाइल नंबर को आधार से वैरिफाई करना है। जिन कस्टमर ने ऐसा नहीं कराया तो उनका नंबर डिएक्टिवेट भी हो सकता है। कस्टमर की इन्हीं मजबूरियों का फायदा कुछ टेलिकॉम कंपनियां उठा रही हैं। जिसकी शिकायत यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) तक पहुंची है। मामले की जांच करने पर अथॉरिटी ने कंपनियों को चेतावनी भी दी है। अथॉरिटी ने कंपनियों को अलर्ट करते हुए कहा है कि वह कस्टमर को परेशान न करे, अगर वे नहीं सुधरेंगे, तो उन पर एक करोड़ रुपए तक पेनल्टी भी लगाई जाएगी। फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

के बाद सभी टेलिकॉम कंपनियों को अपने पहले से मौजूद कस्टमर का आधार के जरिए वैरिफिकेशन करना है। जिसके तहत एक साल की समय दिया गया था। अब सरकार ने फरवरी 2018 की डेडलाइन भी तय कर दी है। यानी इसके बाद वैरिफाई नहीं कराए गए नंबर डिएक्टिवेट

टेलिकॉम कंपनियों पर लग सकती है पेनल्टी

हो जाएंगे। इसी प्रोसेस में यूआईडीएआई के पास कई कंपनियों की शिकायत पहुंची है। जिसमें यह बात सामने आई है कि टेलिकॉम कंपनियां वैरिफिकेशन के नाम पर



कई गलत प्रैक्टिस कर रही हैं। अधिकारी के अनुसार उसे इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि कस्टमर से कंपनियां

वैरिफिकेशन के नाम पेमेंट बैंक अकाउंट भी खुलवा रही हैं। इसके लिए उनसे दो-दो बार बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन कराया जा रहा है। इसके अलावा इस बात की भी शिकायतें आई हैं, कि कंपनियां वैरिफिकेशन के लिए जरूरत से ज्यादा फॉर्म कस्टमर से भरवा रही हैं।

एक अधिकारी के अनुसार इस संबंध में कंपनियों के साथ मीटिंग की गई है। साथ ही उनके खिलाफ मिली शिकायतों के आधार पर फैक्ट्स भी चेक किए गए हैं। जिसके आधार पर कई टेलिकॉम कंपनियों को चेतावनी दी गई है। उनसे कहा गया है कि वह कस्टमर को परेशान न करें। अगर उनके खिलाफ शिकायत आई तो एक करोड़ तक पेनल्टी लगाने के साथ, दूसरे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।